एक नजर में

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ एवं पोषण किट वितरण कार्यक्रम

सिंगरौली। महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना सिंगरौली शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। उसी के तारतम्य में परियोजना सिंगरौली शहरी अंतर्गत कचनी आंगनबाड़ी केंद्र में आज बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र गुप्ता द्वारा की गई। कार्यक्रम में लिंगानुपात, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं लिंग आधारित भेदभाव पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में राजमाता चून कुमारी ट्रस्ट द्वारा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण किट का वितरण किया गया। ट्रस्ट के सहयोगी कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी शैलेंद्र साकेत द्वारा कार्यक्रम की महत्व के बारे में हितग्राहियों को बताया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र गुप्ता परियोजना अधिकारी, दिग्विजय सिंह सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला वर्मा कार्यालयीन स्टाफ नीलकमल गुप्ता व लोकेश मिश्रा मौजूद रहे।

भावान्तर योजना अंतर्गत सरसों का पंजीयन आज से

सिंगरौली। उप संचालक कृषि अजीत सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान भाईयो को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सरसों की फसल को भावान्तर योजनान्तर्गत शामिल किया गया है । भावान्तर योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2025-26 में ई-उपार्जन पोर्टल पर 26 फरवरी से 20 मार्च तक सरसों का पंजीयन किया जायेगा। सरसों का पंजीयन रबी वर्ष 2025-26 में ई-उपार्जन पोर्टल पर रबी गेंहू के लिए निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर ही सरसों का भावांतर योजना अंतर्गत किसान पंजीयन कर सकेंगे । इसके अंतर्गत कृषकों को सरसों का समर्थन मूल्य से कम कीमत पर उपज बिकने पर माडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच में अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा किसानों को दी जाएगी

चना एवं मसूर उपार्जन का पंजीयन 16 मार्च तक

सिंगरौली। उप संचालक कृषि अजीत सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि रबी वर्ष 2025-26 विपणन वर्ष 2026-27 में ई-उपार्जन पोर्टल पर रबी गेंहू के लिए निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर ही 20 फरवरी से 16 मार्च तक चना एवं मसूर का समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है । उन्होंने जिले के कृषक भाईयों से अपील है कि अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्रों पर पहुँचकर चना एवं मसूर फसल उपार्जन के लिए अधिक से अधिक पंजीयन करायें । इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।

तीन साल में ध्वस्त विकास !

लाखों की फेंसिंग कमीशन की भेंट, गुणवत्ता पर गंभीर सवाल

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। विंध्यनगर तिराहा से लेकर यूपी सीमा तेलगवां पुल तक सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यह मार्ग अब विकास की नहीं, बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सड़क के मेंटेनेंस और मरम्मत की जिम्मेदारी एनटीपीसी विंध्यनगर पर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। करीब तीन वर्ष पूर्व चेक पोस्ट तेलगवां के पास पानी के रिसाव को रोकने के लिए लाखों रुपये की लागत से सड़क किनारे फेंसिंग कराई गई थी। उद्देश्य था सड़क को सुरक्षित और मजबूत बनाना, लेकिन घटिया निर्माण और कथित कमीशनखोरी के चलते वह फेंसिंग अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जगह-जगह पीसीसी सड़क टूट गई है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

जोखिम भरा हो गया मार्ग

यह मार्ग ऐश राखड़ ढोने वाले भारी वाहनों का मुख्य रास्ता है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं। भारी दबाव और कमजोर निर्माण के कारण सड़क की परतें उखड़ रही हैं। राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को अब इस मार्ग से गुजरना जोखिम भरा लगने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता और नियमित मॉनिटरिंग होती, तो सड़क की यह दुर्दशा नहीं होती। अब सवाल उठता है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क दो साल भी क्यों नहीं टिक पाई, क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों में दबा रह जाएगा।

भोपाल में अधिवक्ताओं ने न्यायालय भवन के लिए सौंपा ज्ञापन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से विधायक की मौजूदगी में हुई अहम मुलाकात

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला मुख्यालय बैढ़न के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिन बुधवार को भोपाल पहुंचा और विधानसभा परिसर में म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट कर न्यायालय भवन निर्माण में आ रही बजट संबंधी कठिनाइयों को विस्तार से रखा।

यह महत्वपूर्ण मुलाकात सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिससे अधिवक्ताओं को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जगी है। प्रतिनिधिमंडल में जिला अधिवक्ता संघ बैढ़न के अध्यक्ष बृजेंद्र देव पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शाह, रामजी जायसवाल, सुरेंद्र प्रसाद पांडेय, हेम प्रताप तिवारी, संघ के पूर्व सचिव प्रदीप कुमार शाह, संघ के सचिव सुरेश कुमार जायसवाल तथा मन्नान खान शामिल रहे।

सभी अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के समक्ष न्यायालय भवन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और मांग किया कि न्यायिक गतिविधियों व व्यवहारिक दिक्कतें जो आ रही हैं उसमें सुधार किया जाये, ताकि न्यायालयीन व्यवस्था बेहतर हो सके।

बजट के अभाव में प्रभावित हो रहा न्यायालय भवन

अधिवक्ताओं ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का निर्माण कार्य बजट के अभाव में प्रभावित हो रहा है। पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने से निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ गई है, जिससे न्यायिक गतिविधियों के संचालन में भी व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस मुद्दे को लेकर वे पूर्व में कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, किंतु अपेक्षित समाधान नहीं निकल सका। विधायक रामनिवास शाह ने भी मुख्यमंत्री से न्यायालय भवन के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। मुलाकात के बाद अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया कि विधायक के प्रयासों और मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख से शीघ्र ही अतिरिक्त बजट स्वीकृत होगा तथा जिला न्यायालय भवन निर्माण कार्य को नई गति मिलेगी।

गोड़बहरा पंचायत में मजदूरी भुगतान में लापरवाही

आदिवासी मजदूर भटकने को मजबूर

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। जिले के देवसर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गोड़बहरा में मनरेगा के तहत काम करने वाले गरीब आदिवासी मजदूर अपनी मेहनत की मजदूरी के लिए सरपंच और सचिव के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में किए गए कार्यों की मजदूरी अब तक उनके खातों में जमा नहीं हुई है, जिससे वे पंचायत के कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। दुधिया टोला निवासी फूल कुमारी सिंह पति गिरधारी सिंह को 11 दिन, राम सिंह पिता महिपाल सिंह को 14 दिन तथा मालती सिंह माता लल्ली सिंह पिता स्व. सुबरन सिंह को 28 दिन की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इनके अलावा भी कई मजदूर ऐसे हैं, जिनकी मजदूरी लंबित पड़ी है। मजदूरों का आरोप है कि जब वे पंचायत कार्यालय में भुगतान की जानकारी लेने जाते हैं तो सचिव द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि मजदूरी बैंक खाते में भेज दी गई है, जबकि खातों की जांच करने पर किसी प्रकार की राशि जमा नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है, जिसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके बावजूद पंचायत स्तर पर लापरवाही के कारण मजदूरों को समय पर मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। इससे गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुधिया टोला के मजदूर मजदूरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि कई ग्रामीण सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते हैं। अंततः मजदूरों ने अपनी मजदूरी दिलाने के लिए जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों की मांग है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और लंबित मजदूरी का शीघ्र भुगतान कराया जाए।

स्वच्छता केवल ननि की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है

साफ.-सफाई व्यवस्था मजबूत करने नगर निगम की पहल, सामाजिक संस्थाओं व धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम सभागार में ननि आयुक्त सविता प्रधान के नेतृत्व में धर्मगुरुओं, सामाजिक संस्थाओं तथा विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर की स्वच्छता व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने आपसी परिचय के साथ स्वच्छता को जनभागीदारी से सफल बनाने पर जोर दिया और नगर निगम के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। शहर में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, वर्तमान व्यवस्थाओं की कमियों तथा भविष्य में किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों पर खुलकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छता केवल ननि की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही संभव है। उन्होंने लोगों से अपने घर और परिवार से स्वच्छता की शुरुआत करने की अपील की। बैठक में इमरान खान, सुखदेव सिंह, डॉ. एनपी मिश्र, एसडी गर्ग व राजेश नारायण, युवा डॉ. सुमित गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे।

कचरा संग्रहण व्यवस्था को नियमित करें

बैठक में सुझाव दिया गया कि नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाए जाएं, जिनमें संबंधित वार्ड के पार्षद, निगम अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहें। इन समूहों के माध्यम से वार्ड स्तर की समस्याओं जैसे गंदगी, कचरा वाहन का समय पर न पहुंचना या अन्य व्यवस्थागत कमियां की जानकारी तत्काल साझा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को नियमित और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कचरा संग्रहण शुल्क समय पर लेने तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जुर्माना एवं सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता भी बैठक में बताई गई।

सुरक्षा और जागरूकता की अलख जगा रहा हिंडालको महान

नवभारत न्यूज

बरगवां 25 फरवरी। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड महान एल्युमिनियम ने सीएसआर के अंतर्गत सड़क सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा तथा तंबाकू, शराब एवं नशा उपयोग की रोकथाम को लेकर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, जादू एवं कठपुतली शो जैसे प्रभावी एवं जन सुलभ माध्यमों का उपयोग किया गया, जिसे एक पेशेवर जागरूकता दल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी एवं अन्य सामाजिक विषयों पर भी संदेश दिए गए। यह जागरूकता अभियान महान एल्युमिनियम संयंत्र परिसर एवं आसपास के सीएसआर क्षेत्र के ग्रामों में संचालित किया गया, जिसमें 1500 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। स्थानीय लोगों और प्रतिभागियों ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक संदेशों को सरल और प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुँचाने में सहायक होते हैं।

आशुतोष त्रिवेदी के नेतृत्व में हुई जिला शाखा बैठक

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। म.प्र. लिपिक वर्गीय शास. कर्मचारी संघ की जिला शाखा की बैठक आज दिन बुधवार को आयोजित हुई। बैठक में लगभग 50 लिपिक वर्गीय कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने संगठन को सशक्त बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी गठन की आवश्यकता पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि सभी सदस्यों से विचार-विमर्श कर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अगली बैठक 10 मार्च को आयोजित होगी।

उज्ज्वला योजना बना कमाई का जरिया, पात्र को नहीं मिल रहा लाभ

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी उज्ज्वला योजना, पात्रों से कनेक्शन के नाम पर वसूला जा रहा पैसा

नवभारत न्यूज

सरई 25 फरवरी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला गैस योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जिले के सरई तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत निगरी में संचालित इण्डेन गैस एजेंसी मे उज्ज्वला योजना के तहत पात्र आवेदकों को कनेक्शन देने के बदले उनसे एक हजार रुपये वसूल किए जा रहे हैं।

बहन सावित्री साकेत ने आरोप लगाते हुए कहा कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए दिसम्बर में आवेदन किए थे और उस वक्त पांच सौ रुपया लिया गया था, केवाईसी के नाम पर और पांच सौ रुपया गैस के नाम पर लिया गया है। कहा की पैसा देगें तभी गैस मिल पाएगा, नही तो नही मिलेगा। केन्द्र सरकार की महत्वाकंक्षी योजना को गैस एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा निःशुल्क कमाई का जरिया बना दिया गया, बताया तो यह भी जा रहा है की साल-दो-साल से बहने भटक रही है पात्र होते हुए भी अभी तक नही मिल सका गैस कनेक्शन।

घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा गैस चूल्हा

बहनों का कहना है की पहले कुछ हद तक चूल्हा ठीक मिला करता था किन्तु अब बिलकुल घटिया क्वालिटी का चूल्हा दिया जा रहा, जो बहुत कम समय तक चलेगी। भ्रष्टाचार के दलदल में योजनाओं को ढकेल दिया गया, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है जिला प्रशासन एसे मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाई करें।

स्व.श्रवण कुमार वैश्य स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। वार्ड क्रमांक 38 तुलसी बलियरी में स्व. श्रवण कुमार वैश्य की स्मृति में क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वार्ड 38 बलियरी और वार्ड 39 बलियरी के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया।

कड़े संघर्ष के बाद वार्ड 38 तुलसी बलियरी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि वार्ड 39 बलियरी की टीम उपविजेता रही। मुख्य अतिथि अनिल कुमार बैस ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद अनिल कुमार बैस उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पप्पू रॉय, लाल बाबू बैस, पहलाद वैश्य, पंकज कुमार बैस, दीपेश कुमार बैस, राम बाबू बैस तथा पंकज कुमार सिंह सहित वार्ड के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। आयोजन खेल भावना, एकता और आपसी सहयोग का सुंदर उदाहरण बनकर उभरा।

बिना अभिवहन पास पकड़ा गया वाहन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया।

खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में सहायक खनिज अधिकारी रामसुशील चौरसिया की टीम ने बिना अभिवहन पास के अवैध रूप से मुरूम परिवहन करते एक वाहन को पकड़ा। जांच के दौरान ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एमपी 66 जेडएच 8210 आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जप्त कर पुलिस थाना कोतवाली बैढ़न में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं परिवहन के मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, वित्तीय अनियमितता के बाद भी मेहरबानी क्यों?

एक ही प्राध्यापक पर तीन-तीन महाविद्यालयों का प्रभार, आखिर क्यों, चितरंगी में प्राध्यापक मौजूद, फिर भी नहीं मिला दायित्व

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 फरवरी। अंधा बांटे रेवड़ी, चुन-चुन अपने को दे, यह कहावत इन दिनों बैढ़न के डिग्री कॉलेज में चरितार्थ होती नजर आ रही है। छात्र-छात्राओं और शैक्षणिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं कि आखिर किस विशेष आधार पर एक ही प्राध्यापक को तीन-तीन महावि. का प्रभार सौंप दिया गया है।

मामला शासकीय स्व. जगन्नाथ सिंह स्मृति महावि. चितरंगी, मॉडल कॉलेज रंपा और शास. प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बैढ़न से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार एक्सीलेंस कॉलेज बैढ़न में पदस्थ एक प्राध्यापक को न सिर्फ अपने महावि. का प्रशासनिक प्रभारी बनाया गया है, बल्कि चितरंगी और मॉडल कॉलेज रंपा का भी प्राचार्य प्रभार दे दिया गया है। जिला मुख्यालय बैढ़न से चितरंगी की दूरी लगभग 85 किलोमीटर और रंपा की दूरी करीब 25 किमी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि एक ही व्यक्ति तीन संस्थानों की शैक्षणिक व प्रशासनिक

मॉनिटरिंग कितनी प्रभावी ढंग से कर पाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि चितरंगी महावि. में नियमित प्राध्यापक एवं अतिथि विद्वान कार्यरत होने के बावजूद उन्हें प्राचार्य का दायित्व नहीं सौंपा गया। इससे संदेह और गहरा गया है कि नियुक्ति योग्यता और उपलब्धता के आधार पर हुई या फिर व्यक्तिगत समीकरणों के चलते यह फैसला लिया गया। अब निगाहें भोपाल स्थित उच्च शिक्षा विभाग भोपाल पर टिकी हैं। यदि विभागीय अधिकारियों की मौन स्वीकृति या संरक्षण प्राप्त है, तो निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद धुंधली पड़ती दिख रही है। शिक्षा जैसे गंभीर क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है, अन्यथा मेहरबानी और प्रभाव की यह संस्कृति पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देगी।

तीन माह पूर्व प्रभार, अब हटाया

सूत्रों की मानें तो दो-तीन माह पूर्व चितरंगी महाविद्यालय का प्रभार एक अन्य प्राध्यापक को दिया गया था, जिन्हें बाद में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हटा दिया गया। हालांकि चर्चाएं यह भी हैं कि वित्तीय मामलों की डीडीओ शक्ति डिग्री कॉलेज बैढ़न स्तर पर केंद्रित होने के बावजूद कार्रवाई केवल एक व्यक्ति तक सीमित क्यों रही? यदि आर्थिक निर्णयों में उच्च स्तर की भूमिका थी, तो जांच का दायरा व्यापक क्यों नहीं बनाया गया? कैंपस में यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि नए प्रभारी प्राचार्य के रूप में जिम्मेदारी मिलने के बाद संबंधित प्राध्यापक का चितरंगी महाविद्यालय में सीमित दौरा ही हुआ है। ऐसे में शैक्षणिक गतिविधियों, छात्र समस्याओं और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी किस स्तर पर हो रही है, यह स्पष्ट नहीं है।